

एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे आईआईटी

नई दिल्ली/भाषा। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रमों को आईआईटी परिषद की बैठक के बाद नया रूप दिया जाना तय है। अधिकारियों का दावा है कि इन कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। देश के 23 प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों की सर्वोच्च समन्वय संस्था, आईआईटी परिषद ने यह निर्णय पिछले वर्ष अगस्त में हुई अपनी बैठक में लिया। यह बैठक दो वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। जेईई एडवांस्ड परीक्षा को एक बेहतर और कम तनावपूर्ण मूल्यांकन वाला बनाने के उद्देश्य से, आईआईटी परिषद ने परीक्षा को अनुकूल बनाने की संभावना तलाशने की सिफारिश की, जिसमें उम्मीदवार की क्षमता के अनुसार प्रश्न वास्तविक समय में स्वतः तैयार किए जाएंगे।

‘तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना होगा’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर खास ध्यान देना होगा। गडकरी ने सीएसआईआर के ‘प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह’ को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि अपशिष्ट (एगो-वेस्ट) को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है, जिससे न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में पेट्रोलियम-रहित घटक



बायो-बिंदुमेन का इस्तेमाल ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक रूपांतरकारी कदम है। गडकरी ने कहा, एगो-वेस्ट के उपयोग से पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण घटेगा और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर आधारित अर्थव्यवस्था को

मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि वाहन ईंधन में 15 प्रतिशत मिलावट की जाए तो भारत करीब 4,500 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता में बड़ी कमी आ सकती है। गडकरी ने कहा कि फिलहाल दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए अपना आयात घटाने और निर्यात को बढ़ाने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो-बिंदुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने बायो-बिंदुमेन के इस्तेमाल को टिकाऊ विकास, आत्मनिर्भरता और

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वृद्धि की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। गडकरी ने कृषि और निर्माण उपकरण विनिर्माताओं से वैकल्पिक ईंधन और फ्लेक्स-इंजन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में 10 राजमार्ग खंड चिन्हित किए हैं। लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन ईंधन के परिवहन को एक बड़ी चुनौती बताया। गडकरी ने कहा कि भारत को ऊर्जा का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बनना चाहिए। गडकरी ने कहा कि देश हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपए जीवाश्म ईंधन के आयात पर खर्च करता है, जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है।

‘अंतरिक्ष संस्थानों का नेतृत्व संभालने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



अहमदाबाद/भाषा। भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (आईआईए) की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें नेतृत्व संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आईआईए की पहली महिला निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने यहां भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) में आयोजित ‘एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया’ (एसआई) की पांचवीं संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि महिलाओं को संस्थागत और पारिवारिक स्तर पर अधिक समर्थन की जरूरत है। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, अंतरिक्ष अन्वेषण में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के

साथ भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व स्तर पर उनकी उपस्थिति अभी कम है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने कहा कि लचीले कार्य घंटों जैसी सहायक संगठनात्मक नीतियां अधिक से अधिक महिलाओं को अपना करियर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। उन्होंने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि देश अपने प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधनों का लगभग 50 प्रतिशत खोने का जोखिम नहीं उठा सकता और देश की बेहتری के लिए महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल ने तिरुपति मंदिर में पूजा-अर्चना की

तिरुपति/भाषा। मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल ने बुधवार को तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। टीटीडी के अधिकारियों ने गोखूल का स्वागत किया और उन्हें मंदिर में दर्शन के लिए ले गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “गोखूल ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। इससे पहले टीटीडी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें दर्शन के लिए ले गए थे।” दर्शन के बाद, टीटीडी के अधिकारियों ने उन्हें (मॉरीशस के राष्ट्रपति को) रंगनायकुला मंडपम में रेशमी वस्त्र, प्रसाद और भगवान वेंकटेश्वर की एक तस्वीर प्रदान की। टीटीडी तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक अनुसूचक निकाय है।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जरूरी मुद्दों पर चुप हैं, पीडीपी की आलोचना में व्यस्त हैं : महबूबा मुप्ती



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुप्ती ने बुधवार को केंद्रशासित प्रदेश के लोगों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा।

महबूबा ने अपने पिता एवं पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की दसवीं पुण्यतिथि पर दिए गए संक्षिप्त भाषण में कहा कि महबूबा उनकी पार्टी (पीडीपी) के प्रति जरूरत से ज्यादा चुनूनी हैं और अपना ज्यादातर समय केवल उसकी आलोचना करने में ही व्यस्त रहते हैं।

महबूबा मुप्ती ने कहा, “आज, यदि कोई युवा अपनी बात रखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हजारों लोग (विभिन्न) जेलों में बंद हैं। जब मैं इन मुद्दों को लेकर अदालत गई तो मुझे कहा गया कि मैं कौन होती हूँ इस पर बोलने वाली। यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा?” मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “यह उमर की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता वह (मुख्यमंत्री) अपने 50 विधायकों और कई सांसदों के साथ किस दुनिया में रहते हैं कि वह इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते? वह सिर्फ पीडीपी की आलोचना करते हैं, वह पीडीपी के प्रति चुनूनी हैं।”

भारत की जीडीपी वृद्धि अगले वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान: रिपोर्ट

मुंबई/भाषा। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन शैक्स ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 7.3 प्रतिशत दर से कम होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से बुधवार को जारी राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गोल्डमैन शैक्स की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास आगे ब्याज दरों में कटौती की सीमित गुंजाइश बचेगी। रिपोर्ट कहती है, हमें वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने वाले निजी पूंजीगत व्यय या नए निवेश पिछले कुछ वर्षों में सुस्त रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2025 में अमेरिका की ओर से लगाए गए उच्च शुल्क का भी पूंजीगत व्यय पर असर पड़ा।

सरकार का फरवरी में संसद में बीज विधेयक पेश करने का लक्ष्य: कृषि सचिव



नई दिल्ली/भाषा। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के पहले चरण में फरवरी में संसद में बीज विधेयक 2025 पेश करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हमें बीज विधेयक 2025 के लिए सुझावों सहित 9000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम इन पर विचार करेंगे और ‘कैबिनेट नोट’ में इन्हें शामिल करेंगे। हमारा लक्ष्य इस विधेयक को बजट सत्र के पहले चरण में पेश करना है।”

सचिव ने कहा कि मंत्रालय संसद के अवकाश के बाद कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को पेश करने की योजना बना रहा है। बीज विधेयक, 1966 के बीज अधिनियम का स्थान लेगा। इसमें गुणवत्ता और पैकेट पर क्यूआर कोड जैसे आधुनिक मानकों के साथ ‘ट्रेसबिलिटी’ सुनिश्चित करने के लिए बीज किस्मों, डीलर और उत्पादकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। इसमें निगरानी के लिए केंद्रीय एवं राज्य बीज समितियों की स्थापना भी प्रावधान है। साथ ही किसानों को बिना पंजीकरण के कृषि में संरक्षित बीजों को रखने और आदान-प्रदान करने की अनुमति दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर उल्लंघनों के लिए जुर्माना एक लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक से लेकर कारावास तक हो सकता है। यह मामले की गंभीरता के आधार पर लगाया जाएगा। इसमें तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।



आंध्र प्रदेश : टोल प्लाजा के निकट बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयलूर (आंध्र प्रदेश)/भाषा। विशाखापत्तनम जा रही एक बस में बुधवार तड़के पूर्वी गोदावरी जिले के गमन ब्रिज टोल प्लाजा के निकट आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 10 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को वाहन के आग की चपेट में आने से पहले सुरक्षित बाहर निकाल

लिया गया। पुलिस के अनुसार, बस जब रात लगभग दो बजे टोल प्लाजा के निकट पहुंची, तभी उसमें आग लग गई। एक पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, इस घटना में किसी के हलाहट या घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर चालक का कहना है कि डायनामो में आई तकनीकी खराबी के कारण आग लगी। टोल प्लाजा के निकट बस रोकने के बाद चालक ने इंजन की जांच की, जहां उसे चिंगारियां दिखाई दीं। इसके

बाद उसने तुरंत यात्रियों और कर्मचारियों को सतर्क किया, जो तुरंत बस से उतर गए। पुलिस ने कहा कि चालक की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। चालक दल ने लगभग 10 मिनट के भीतर यात्रियों को उनके सामान सहित सुरक्षित बाहर निकाल ली। अधिकारियों ने प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था की, जबकि यातायात को नियंत्रित किया गया और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू की गई।

बेहतर करियर के लिए 52% भारतीयों ने जताई विदेश जाने की मंशा : रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बेहतर करियर एवं पैसे कमाने के लिए युवाओं में भारत से विदेश जाने का मजबूत रुझान देखा गया है। सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक प्रतिभागियों ने विदेश जाने के बारे में मंशा जतायी।

एआई-सक्षम वैश्विक प्रतिभा आवाजाही मंच टर्न ग्रुप के हाल के एक सर्वेक्षण में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विदेश जाने पर

विचार करने या इसकी सक्रिय तैयारी करने की बात कही। यह सर्वेक्षण देशभर में करीब 8,000 लोगों से बातचीत पर आधारित है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय विकास भारत से बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा। करीब 46 प्रतिशत लोगों ने इस वजह से विदेश जाने की मंशा जताई। इसके बाद बेहतर करियर की तलाश के लिए 34 प्रतिशत लोग विदेश जाने को तैयार दिखे। इसके अलावा व्यक्तिगत सपने और वैश्विक अनुभव भी क्रमशः नौ



प्रतिशत और चार प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए कारण रहे। रिपोर्ट कहती है कि विदेशी प्रवास को लेकर भारतीयों की

पसंद में भी बदलाव आ रहा है। करीब 52 प्रतिशत लोगों ने समय के साथ अपनी पसंदीदा जगह बदली है, जबकि 43 प्रतिशत ने

अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता जताई। जर्मनी 43 प्रतिशत लोगों की पसंद के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद ब्रिटेन 17 प्रतिशत, जापान नौ प्रतिशत और अमेरिका चार प्रतिशत लोगों की पसंद रहा। विदेश जाने की इच्छा रखने वाली भारतीय नर्सों के रुझान में क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिली। विदेश जाने वाली 61 प्रतिशत नर्स प्रमुख महानगरों से बाहर से संबंधित हैं जबकि दिल्ली-एनसीआर से 17 प्रतिशत नर्सों ने विदेश जाने की बात कही। हालांकि, करियर एवं पैसे के

लिए विदेश जाने की राह में चुनौतियां बनी हुई हैं। भाषा की जरूरतों को 44 प्रतिशत लोगों ने सबसे बड़ी बाधा बताया। इसके अलावा, अनैतिक भर्ती, मार्गदर्शन का अभाव, अधिक खर्च और लंबी प्रक्रियाएं भी प्रमुख समस्याओं के रूप में उभरीं। टर्न ग्रुप के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अविनव निगम ने कहा, भारतीय प्रतिभा वैश्विक करियर के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए पारदर्शी, नैतिक और शुल्क-शुल्क वाली भर्ती व्यवस्था जैसे समर्थनकारी कदम उठाने की जरूरत है।

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक दूरदराज के गांव में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ बुधवार शाम बिलावर के काहगा गांव में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने दो. तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, एसओजी कठुआ ने कठुआ के कमांध नाला के जंगल में आतंकवादियों से मुठभेड़ की है। सूत्रों के मुताबिक, शाम करीब चार बजे बिलावर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमांध नाला में स्थानीय लोगों ने एक आतंकवादी को देखा। सूत्रों ने कहा, यह वही आतंकवादी हो सकता है जिसे आज सुबह धनुष पेरौल पर देखा गया था। अधिकारियों ने कहा आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अतिरिक्त बल को गांव में भेजा गया है।

हिमाचल प्रदेश: आग में 200 साल पुराना जुन्गा महल जलकर खाक हो गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला/भाषा। शिमला से लगभग 26 किलोमीटर दूर जुन्गा में स्थित 200 साल पुराना एक ऐतिहासिक महल बुधवार को भीषण आग की चपेट में आने से नष्ट

हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, दोपहर करीब 1:00 बजे जे भड़की इस भीषण आग ने कुछ ही समय में पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि आग लगने के सटीक कारण और इस घटना में हुए कुल नुकसान का अभी पता लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस महल का निर्माण 1800 के दशक में तत्कालीन क्यॉथल रियासत के शासकों ने करवाया था।

वैज्ञानिकों ने एआई आधारित मॉडल बनाया, नींद के आंकड़ों से बीमारी के खतरे का लगायेगा पता



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अनुसंधानकर्ताओं ने कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया है जो नींद के आंकड़ों से 100 से अधिक अलग-अलग स्वास्थ्य स्थिति के खतरे का अनुमान लगा सकता है। एक शोध में इसकी जानकारी दी गई है। इस मॉडल को ‘स्लीपएफएम’ नाम दिया गया है, जिसे अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने मिलकर बनाया है। इस अनुसंधान में 65,000 लोगों ने हिस्सा लिया और उनसे एकत्र किए गए करीब छह लाख घंटे के नींद के आंकड़ों पर इसे प्रशिक्षित किया गया है। ‘नेचर मेडिसिन’ नामक पत्रिका में छपे एक पेपर में बताया गई इस कृत्रिम मेधा प्रणाली को शुरू में नींद के विश्लेषण से जुड़े मानक कार्यों पर परखा गया था, जैसे नींद के अलग-अलग चरण को रिकार्ड करना या स्लीप एपनिया की गंभीरता का पता लगाना। इसके बाद इस मॉडल का इस्तेमाल नींद के आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली बीमारी का अनुमान लगाने के लिए किया गया, जिसमें हेल्थ रिकार्ड का डेटा एक स्लीप क्लिनिक से लिया गया था। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि स्वास्थ्य रिकार्ड में 1,000 से ज्यादा बीमारियों की श्रेणी रखी गई और मरीज के सोने के आंकड़ों

का इस्तेमाल करके 130 बीमारियों का अंदाजा सटीकता से लगाया जा सका। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ‘मनोरोग एवं व्यवहार विज्ञान’ विभाग में स्लीप मेडिसिन के प्रोफेसर और सीनियर लेखक इमैनुएल मिग्रोट ने कहा, “जब हम नींद का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सारे सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं। यह एक तरह की जंगल फिजियोलॉजी है जिसका हम एक ऐसे व्यक्ति पर आठ घंटे तक अध्ययन करते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। इसमें बहुत सारा डेटा होता है।” पॉलीसोम्नोग्राफी – जिसे नींद के अध्ययन में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है – नींद का डेटा इकट्ठा करने का एक आम तरीका है जो सेंसर का इस्तेमाल करके दिमाग की एक्टिविटी, दिल के काम, सांस के सिग्नल और आंखों की हरकतों के साथ-साथ दूसरी चीजों को रिकॉर्ड करता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि एआई मॉडल कई तरह के डेटा को शामिल करने में सक्षम था – जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी), इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी), पल्स रीडिंग और सांस लेने का एम्पलीट्यूड – और यह पता लगाने में कि वे एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि एआई प्रणाली के अनुमान केंसर, प्रेग्रेसी की दिक्कतों, सर्कुलेटरी बीमारियों और मेटल डिसऑर्डर के लिए खास तौर पर बहुत अच्छे पाए गए।

ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है ‘जी राम जी’ कानून : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि यह ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस कानून को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ‘वीबी-जी राम जी’ कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि ‘वीबी-जी राम जी’ कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा तथा यह कानून ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत की रूपरेखा से जोड़ेगा और राजस्थान को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मनरेगा’ को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत मंशा की वजह से मनरेगा के तहत किए गए अधिकांश कार्य गांवों की समग्र

विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए, जिनमें अस्थायी सड़कों, अहुरी जल संरचनाओं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य करवाए जाते थे, जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी। शर्मा ने कहा कि मनरेगा में फर्जी और डुन्नीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच पड़ताल के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण ‘सोशल ऑडिट’ केवल औपचारिकता बनकर रह गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कानून इन सभी कमियों को दूर किया गया है और अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर नौ प्रतिशत किया गया है ताकि पर्याप्त स्टॉफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ‘वीबी-जी राम जी’ अधिनियम में हर वर्ष के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया जाएगा तथा मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। शर्मा ने कहा, कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रामक प्रचार है। वह हमेशा झूठ व भ्रामक प्रचार में आगे रहती है।



गरीबी को दूर करने का शिक्षा ही सबसे सशक्त माध्यम : राज्यपाल बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बीएन संस्थान की शुरुआत एक साधारण पाठशाला के रूप में हुई थी, जो आज एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में देशभर में अपनी पहचान बना चुका है। यह संस्थान शिक्षा के माध्यम से समाज के उत्थान की उस सोच को साकार कर रहा है, जिसकी नींव मेवाड़ के प्रेरणापुरुष महाराणा भूपाल सिंह ने रखी थी। उन्होंने कहा कि महाराणा भूपाल सिंह शिक्षा और जनकल्याण में गहरी आस्था रखते थे तथा उन्होंने विभिन्न आयामों में उज्ज्वल शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1945 में उन्होंने अपने महल के भीतर औषधालय की स्थापना कर जरूरतमंदों को उपचार उपलब्ध करवाया, जो उनकी संवेदनशीलता और दूरदृष्टि का प्रमाण है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को उदयपुर में आयोजित भूपाल नोबल्स (बीएन) विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में

संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के 90 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि, 47 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक सहित कुल 2025 विद्यार्थियों को विभिन्न संकायों की डिग्रियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के शासक स्वयं को एकलिंगजी भगवान का प्रतिनिधि मानकर शासन करते थे। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया और मोहम्मद बिन कासिम को ईरान की सीमाओं तक खदेड़ दिया था। यह इतिहास आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है। बागड़े ने कहा कि मेवाड़ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में बीएन संस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा के माध्यम से इस संस्थान ने जनजातीय अंचलों में ज्ञान का आलोक फैलाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा से जोड़ना समय की मांग है, ताकि वे मुख्यधारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। वंचित और पिछड़े वर्ग का उत्थान आज देश की

सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि गरीबी को यदि स्थायी रूप से दूर किया जा सकता है तो उसका सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही है। केवल डिग्री प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की जिद और सीखते रहने का संकल्प होना चाहिए। सफलता के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं। विद्यार्थी निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएं, अपनी सोच और दृष्टि को व्यापक बनाएं तथा स्वयं को सफल देखने का मानस तैयार करें, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी तरुण भारत के कंधों पर है। देश का स्वर्णिम गौरव विश्वविद्यालयों से ही निकलेगा और तक्षशिला व नालंदा जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्रों का वैभव पुनः लौटे ऐसी भावना विद्यार्थियों में होनी चाहिए। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सहायता करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से विगत 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो सुशासन और समावेशी विकास का उदाहरण है।

किसानों की महापंचायत, इथेनॉल फैक्ट्री के लिए हुआ समझौता रद्द करने की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध और किसानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को संग्रिया करके की धान मंडी में किसान महापंचायत हुई। इस महापंचायत में राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के किसान नेता व संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। ‘इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ-क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति’ के बैनर तले किसान नेताओं ने प्रस्तावित फैक्ट्री से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) को रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। महापंचायत से पहले किसानों ने नगर परिषद कार्यालय में बने किसान स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अगली महापंचायत 11 फरवरी को हनुमानगढ़ जिले तलवाड़ा झील गांव में होगी। किसान नेताओं ने महापंचायत में कहा कि प्रस्तावित इथेनॉल कारखाने से क्षेत्र की खेती, भू-जल और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसानों की सहमति के ऐसे उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसे किसी भी सूत्र में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

किसान जत्थेबंदी (उग्राहां) के वरिष्ठ नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहां ने कर्ज माफी और किसानों-मजदूरों की बहाल आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार की नीतियां आम जनता के लिए नहीं बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों के हित में बनाई जा रही हैं। उग्राहां ने कहा, वर्ष 2012 से 2018 के बीच औद्योगिक घरानों का 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ किया गया जबकि किसानों पर कुल कर्ज लगभग 12 लाख करोड़ रुपये ही है। अगर सरकार वाहती तो इसी राशि से देश के सभी किसानों का कर्ज पूरी तरह समाप्त कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, किसानों की कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समय की सबसे बड़ी जरूरत है। देश में धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सरकार की इच्छाशक्ति की। उग्राहां ने मजदूरों के कर्ज को भी पूरी तरह खत्म करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार किसानों और मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा और किसान-मजदूर सड़क से संसद तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी किसान को डराने या दबाने की कोशिश की गई, तो पूरा हनुमानगढ़ जिला एकजुट होकर विरोध करेगा।



किसानों की आमदनी में वृद्धि से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत : वी. श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उन्हें कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य रखे। उन्होंने कहा कि ग्राम के आयोजन से प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर इनके माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृष क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे। मुख्य सचिव ने ग्राम के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, राजस्व, उद्योग, पर्यटन आदि विभागों को आपसी

समन्वय से काम करने के लिए कहा। इस आयोजन में कृषकों की भागीदारी के लिए मुख्य सचिव ने कृषकों का पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, जिससे प्रगतिशील किसान ज्यादा से ज्यादा भाग लें और नवीन तकनीकों एवं नवाचारों का फायदा ले सकें। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने पीपीटी के माध्यम से ग्राम की तैयारियों पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम के आयोजन में पूरे प्रदेश से 50 हजार से ज्यादा कृषक भाग लेंगे, जिसमें राज्य के एवं संबद्ध क्षेत्रों की कृषि क्षमताओं एवं संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा, देश-विदेश में रोड शो का भी आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषक गोष्ठियों, प्रदर्शनी, सेमिनार, काफ्रेन्स, क्रेता-विक्रेता बैठकों व बिजनेस बैठक का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रदर्शक

एवं कम्पनियां, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडलों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर के संस्थानों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी। उल्लेखनीय है कि ग्राम के आयोजन का उद्देश्य विश्व स्तर पर उपलब्ध कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों और नवाचारों को प्रदेश में किसानों तक पहुंचाना है। जिससे प्रदेश के कृषक नवीन तकनीक अपनाकर अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकेंगे और प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, राजस्व, उद्योग, पर्यटन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वित्त, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया गया।

चेन्नई की संस्था ने फर्जी फायर टेक्नीशियन डिप्लोमा से खेला करोड़ों का खेल, डायरेक्टर गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप विशाल बंसल ने बताया कि भारतीय नौसेना की फायर टेक्नीशियन पद की प्रतियोगी परीक्षा-2025 में शामिल अभ्यर्थियों को बैकडेट फर्जी डिप्लोमा और अंकात्मिका उपलब्ध कराने के मामले में चेन्नई की भारत सेवक समाज संस्था के डायरेक्टर अरुण ग्राना मोईसन को गिरफ्तार किया गया है। एस.ओ.जी., जयपुर द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार, संस्था ने ए.एस. फायर एवं सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट, तुंगला, करौली के साथ मिलकर वर्ष 2023-24 के डिप्लोमा और अंकात्मिकाएं बिना किसी प्रशिक्षण के जारी की। केवल 12वीं की अंकात्मिका और आधार कार्ड लेकर 2-3 दिन में फर्जी डिप्लोमा प्रदान किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि भारत सेवक समाज संस्था ने खुद को योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अधिकृत स्किल डेवलपमेंट कोर्स संचालक बताकर आमजन को भ्रमित किया। संस्था के पास

कोई प्रशिक्षण सेटअप नहीं था, केवल ऑफिस स्तर का सेटअप था। सैकड़ों कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों को जोड़कर संस्था ने बैकडेट डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र जारी कर करोड़ों रुपये की अवैध आय अर्जित की। कॉलेजों से प्रति अभ्यर्थी 2,000 रुपये तथा प्रति कॉलेज 7,70,000 से छ1,00,000 वसूले गए। अनुमानित तौर पर 10,000 से अधिक कॉलेजों को जोड़कर यह अवैध गतिविधि संचालित की गई। जांच में यह भी पता चला कि संस्था के चेयरमैन बी.एस. बालचंद्रन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं। अरुण ग्राना मोईसन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य दोषियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। विशाल बंसल ने चेतावनी दी कि भारत सेवक समाज द्वारा जारी किसी भी प्रमाण-पत्र को किसी मान्यता प्राप्त कोर्स के समकक्ष नहीं माना जा सकता, अतः नियोजन संस्थाओं से आग्रह है कि ऐसे डिप्लोमा धारकों के चयन से पूर्व प्रमाण-पत्रों का पूर्ण और विधिवत सत्यापन अवश्य करें।



नारी चौपाल बना महिला सशक्तिकरण का सशक्त मंच

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को सशक्त आधार देने की दिशा में सक्षम जयपुर अभियान के तहत नारी चौपाल कार्यक्रम प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उपखण्ड स्तर पर आयोजित इन चौपालों ने महिलाओं को संवाद, सहभागिता और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच प्रदान किया है। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निदेशानुसार बुधवार को बरसी उपखण्ड में नारी चौपाल का भव्य

आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता ने आयोजन को प्रेरणादायी बना दिया। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मृणाल कुमार एवं उपखण्ड अधिकारी डॉ. परिमा शर्मा की गरिमायुक्त उपस्थिति में आयोजित चौपाल में महिलाओं ने आत्मविश्वास, हुनर और नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्रड नाटक एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी प्रस्तुतियों ने चौपाल को जीवंतता प्रदान की। हम होंगे कामयाब और मेरा काममेरा सम्मान जैसी

प्रस्तुतियों के माध्यम से महिलाओं ने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का सशक्त संदेश दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव साझा किए जाने से उपस्थित प्रतिभागियों को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिली। नारी चौपाल में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने महिलाओं से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर लगाए गए सहायता काउंटरों के माध्यम से महिलाओं को योजनाओं से जुड़ा मार्गदर्शन और सहयोग भी उपलब्ध कराया गया।

योग्यजनों के लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है : अविनाश गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को उन सरकारी या गैर सरकारी शोध संस्थानों, संगठनों एवं व्यक्तियों के प्रस्तुतिकरण देखे, जिन्होंने विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं सम्बल देने के लिए कृत्रिम अंग या उपकरण की गुणवत्ता के संबंध में शोध किए हैं। मुख्यालय अख्येककर भवन में आयोजित इस अहम बैठक में मशहूर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विशेष योग्यजनों के लिए काम आ रहे कृत्रिम अंगों और उपकरणों को अत्याधुनिक और सहज बनाने के शोध विचार और सुझाव संबंधी विचार रखे। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट



घोषणा में राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से आर्टिफिशियल लिंब्स और इक्स्प्लैन्ट की गुणवत्ता के संबंध में शोध की घोषणा की थी। इसी की अनुपालना में संस्थानों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। उन्होंने कहा राज्य सरकार की मंशा है कि विशेष योग्यजनों को मिलने

वाले उपकरण गुणवत्तायुक्त हों, उपयोगी हों और पहले से अधिक सहज हों हों। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐसा नवाचार करने वाला राजस्थान अकेला प्रदेश है, जहां विशेष योग्यजनों के लिए सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने उपकरणों और

अंगों को और अधिक हल्का, किफायती तथा उपयोग में सुविधाजनक बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शोध संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास विद्यार्थियों के जीवन में स्वावलंबन, सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मददगार साबित होंगे।

कड़ाके की सर्दी जारी, अनेक जगह घना कोहरा छाया रहा

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है जहां बुधवार सुबह भी अनेक इलाके घने कोहरे में रहे। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर जारी रहने तथा घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को सुबह बताया कि बीते चौबीस घंटे में राज्य में अनेक जगह घना कोहरा दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी घना कोहरा छाया रहा। राज्य के अनेक इलाकों में लगातार शीतलहर व शीत दिवस दर्ज किया गया है। बीते चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान सीकर में 4.5 डिग्री, सिराही में 4.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 4.9 डिग्री, फलोदी में 5.8 डिग्री, अजमेर में 5.9 डिग्री, अलवर में 6.1 डिग्री, गंगानगर व चूरू में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.5 डिग्री व 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बूंदी, करौली, दोरा और सवाई माधोपुर में आज तथा कल शीत दिवस रहने व घना कोहरा छाप रहने की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शीत दिवस तब घोषित किया जाता है जब

अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। राजधानी जयपुर व आसपास के इलाकों में बुधवार दोसरे दिन सुबह घना कोहरा छाया रहा। राज्य में अनेक जगह घने कोहरे से दुश्चला ‘शून्य’ तक रही और इसका असर आवागमन के साथ साथ सामान्य जनजीवन पर पड़ा। तापमान में गिरावट और धूप नहीं निकलने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजमार्ग पर वाहन धीमी गति से चलते दिखे। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने शहरों में कई जगह ‘रैन बरसे’ बनाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा आगामी दिनों में अनेक जगह सुबह के समय घना कोहरा व शीत दिन दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी एक-दो दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट हो सकती है। राज्य में शीतलहर जारी रहने की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व सीकर सहित दर्जन भर से अधिक जिलों में स्कूलों में विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए शीतकालीन छुट्टियां बढ़ा दी हैं।

अमित शाह 10 को आरंभ में जयपुर, नवनिर्वाचित कांग्रेसियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 10 जनवरी को आरंभ में नव चयनित कांग्रेसियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वितरित करेंगे।

पुलिस महकमे ने नव चयनित कांग्रेसियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलग-अलग जिलों के पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों के नव चयनित कांग्रेसियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। सभी नव चयनित कांग्रेसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 9 जनवरी की शाम तक जयपुर पहुंच जाएं, ताकि 10 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम को लेकर आरपीए परिसर में सुरक्षा, व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से जुड़ी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

फिल्म की तस्वीरी टीम भी उज्जनी ही दमदार हैनसारन अर्थात् विजेता राजीव रीत सिनेमेटोग्राफी संभाल रहे हैं, संगीत में बरि बसूर का जादू होगा, एडिटिंग की कमाना प्रोड्यूसर कुलकर्णी के हाथ में है और प्रोड्यूसर डिजाइन टीपी आबिने ने किया है। हाई-आवंटन एक्शन को हॉलीवुड के महशूर एक्शननारनायक जेजे पेरे, जिन्हें जाना विक के लिए जाना जाता है, के साथनेनेलन अर्थात् विजेता जोड़ी अंवरिती और केया खाम्माकाळी ने कोरियोग्राफ किया है। वेनकट के नारायण और यश द्वारा केवीएन प्रोडक्शंस और मॉनस्टर माडिफिकैशंस के बैनर तहत बनी काविक की भव्य थिएट्रिकल रिलीज 19 मार्च 2026 को तय है। यह लॉन्ग पैरिट्रिक फिल्म होगा, जब ईश, आगे और गुडी पड्या एक साथ आएंगे और काविक बड़े पड पर जश्न को और भी बड़ी बनाने के लिए पूरी तरफ तैयार होगा।

